विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) वर्ष 1996-97 के लिए 16 रा०वि०बो० के वार्षिक लेखे दर्शाते हैं कि केवल 3 रा०वि०बो० नामशः एएसईबी, बीएसईबी, और एमईएसईबी में आर्थिक सहायता को गिनती में रखते हुए, घाटा हुआ है।

(ख) विद्युत आपूर्ति की लागत तथा वसूली के मध्य का विशाल अंतर रा०वि०बो० का असंगत टैरिफ ढांचा विद्यमान संयंत्रों की क्षमता समुपयोजन का निम्न स्तर तथा उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां इन घाटों का मुख्य कारण है।

(ग) भारत सरकार राज्यों में विद्युत के वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह रा०वि०बो०/राज्य विभाग/कंपनी द्वारा किया जाता है। बिजली की चोरी और अवैध कनेक्शनों को रोकना उनकी जिम्मेवारी है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 को 1986 में संशोधित किया गया था जिसमें बिजली चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया था जिसमें निर्धारित दंड 3 वर्ष की कैद अथवा कम से कम 1000 रुपए का दंड अथवा दोनों हैं।

कुछ बिजली बोर्डों में, चोरी को रोकने के उपाय शुरू किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:—

(i) मीटरों का अब संख्यापित मोहर के साथ टैम्पर-प्रूफ मीटरों में लगाया जा रहा है।

(ii) ऊर्जा के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए आकस्मिक छापे डालने के लिए विशेष सतर्कता दस्तों का गठन किया गया है।

Clearance to Pending Power Projects in Gujarat

1819. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat has submitted a number of power projects for the approval of the Central Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of those out of the above which have been approved by the Central Government and of those which are under consideration;

(d) whether any additional information has been asked for or any joint meeting with the State Government would take place; and

(e) if so, the details thereof along with the amount sanctioned and the expected time for generation of power by these projects?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) The projects received from the Government of Gujarat which have been given techno-economic clearance by the CEA and those which are under consideration are as follows:

Sl. No.	Name of the Project	Capacity (MW)
CEA Cleared/appraised:		
1.	Paguthan CCGT (M/s Gujarat Torrent Energy Corpn. Ltd.) (Bharn.)	654.7
2.	Gandhi Nagar Extn. (Unit 5)—M/sGSECL (Gandhi Nagar)	1×210 = 210
3.	Wanakobri Extn. (Unit 7)—GSECL (Kheda)	1×210 = 210
4.	Hazira CCGT (M/s Essar Power Ltd.) (Surat)	515
5.	Petro Chemical Complex Power Plant at Baroda (GIPCL) (Baroda)	167
6.	Surat Lignite TPP (M/s GIPCL) (Surat)	2×125 = 250
DPR under examination in CEA:		
1.	Jamnagar TPP (Ph. I) (M/s Reliance Power Ltd.)	2×250 = 500

(d) and (e) Seventeen projects received from the Government of Gujarat were returned for want of necessary clearances/ inputs for grant of Techno-Economic Clearance. Government of Gujarat also recommended in August, 1998 some liquid fuel based projects for grant of fuel linkages. The State Government were requested to revise their proposals in this regard in accordance with the modified policy of Government of India on liquid fuel based power projects.